



'FREQUENT HIKES IN TAX DISRUPTING'

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, SEPT. 17

Consumers are getting restive about a three year high in petrol and diesel prices as they feel that the concept of market-determined rates was tampered with by frequent tax hikes when the crude oil prices fell steeply, said industry chambers on Sunday.

It noted if the prices are market determined, the retail prices should have been less than ₹40 a litre. It pointed that even after rising in the last three months, crude oil prices are mere half of \$107 per barrel in May, 2014.

"It is true that the international crude oil prices have shot up by about 18 per cent from \$45.60 per barrel, taking the pump prices of petrol in Delhi (for instance) to ₹70.39 per litre from ₹65.40 three months ago. The increase in the retail prices is far less than hike in crude oil, but then the consumer is not willing to compare the crude prices of \$45.60 in June versus \$54 per barrel today. He would confront you with \$107 per barrel of crude in May, 2014 and the pump price of ₹71.51 per litre on June 1, 2014," said Assocham.

With \$107 per barrel, the retail price of auto fuel was 71.51 per litre, then how come it is about the same when the Indian basket of crude is trading at half that level at 53.83 per barrel, the consumers would ask, said the chamber.

It said, even though the pricing regime has been linked to market determined rates, hike in taxes in the form of excise and sales tax or VAT by the Centre and states have distorted the path of reforms.

त्योहारों में 15% बिक्री बढ़ने की उम्मीद, ई-कॉमर्स में 30% रहेगी ग्रोथ : एसोचैम

■ नोटबंदी और जीएसटी के बाद उपभोक्ता खर्च करने को तैयार

धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया | नई दिल्ली

नवरात्रि से नववर्ष तक त्योहारी सीजन में कंज्यूमर सेंटीमेंट बेहतर रहेगा। इस दौरान बीते वर्ष की तुलना में बिक्री 12-15% बढ़ने की उम्मीद है। मॉल्स में 10-12% ग्रोथ देखने को मिलेगी, जबकि ई-कॉमर्स बिजनेस में 30% तक बढ़ोतरी संभव है। उद्योग चैंबर एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने यह जानकारी दी। जल्द ही एसोचैम इस संबंध में अपनी स्टडी रिपोर्ट जारी करेगा।

रावत ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद उपभोक्ता त्योहारी सीजन में ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं। कंज्यूमर गुड्स कंपनियों को उम्मीद है कि उपभोक्ता 15-25% अधिक खर्च करेंगे। डिस्काउंट, स्कीम और अन्य मार्केटिंग गतिविधियों के कारण मॉल्स में लोगों की संख्या बढ़ेगी। ई-कॉमर्स बिजनेस

इन्फ्रा में तेजी से निवेश बढ़ाए सरकार : अलघ

पूर्व केंद्रीय मंत्री और अर्थशास्त्री डॉ. वाय.के. अलघ ने कहा कि यूरोप-अमेरिका की तुलना में भारत में ब्याज दर अधिक होने और शेयर बाजारों में बेहतर रिटर्न के कारण विदेशी मुद्रा अधिक आ रही है। सीमेंट, ऑटो जैसे सेक्टर का प्रदर्शन बेहतर है। सरकार को इन्फ्रा में निवेश तेजी से बढ़ाना चाहिए, इससे कॉरपोरेट निवेश बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार 400 अरब डॉलर को पार कर गया है।

बेहतर कर रहा है। इस बार जीएसटी के बावजूद कंपनियां विभिन्न उत्पादों पर डिस्काउंट और ऑफर देंगी और अनुमान है कि इस दौरान इनका व्यापार 30% बढ़ेगा।

रावत ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश काफी बढ़ा है। स्टील, सीमेंट,

टैक्स घटने का निर्यातकों को मिलेगा लाभ : फियो

निर्यात में लगातार दूसरे माह वृद्धि हुई है। अगस्त में बीते वर्ष के मुकाबले निर्यात में 10.29% की बढ़ोतरी हुई है। निर्यातकों के संगठन फियो के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, कॉटन यार्न, केमिकल्स जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण निर्यात में बढ़ोतरी हुई। जीएसटी में कुछ वस्तुओं पर टैक्स 12% से घटाकर 5% करने से भी एक्सपोर्टों को लाभ मिलेगा।

कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में वृद्धि दर्ज की जा रही है। एक्सपोर्ट में भी सुधार है।

हेल्थ, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, एफएमसीजी और सर्विसेज सेक्टर में रोजगार के नए मौके निकल रहे हैं। इन सबकी झलक त्योहारी सीजन में दिखेगी।

एसोचैम ने कहा...

पेट्रोल, डीजल के दाम में कटौती की जरूरत

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली. देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे उपभोक्ता चिंतित हैं। इसको लेकर एसोचैम का मानना है जब इन उत्पादों पर लगने वाले करों में बार-बार फेरबदल किया जा रहा हो तो बाजार आधारित कीमतों की अवधारणा का कोई मतलब नहीं है। अब वक्त आ गया है कि कीमतों में कटौती किया जाए। एसोचैम ने कहा कि 2014 के मई में कच्चे तेल की कीमत 107 डॉलर प्रति बैरल थी, उस वक्त अभी से सस्ता



पेट्रोल मिल रहा था। एसोचैम ने अपने रिपोर्ट में कहा कि जब कच्चे तेल की कीमत 107 डॉलर प्रति बैरल थी, तो देश में यह 71.51 रुपए लीटर बिक रही थी। अब जब यह घटकर 53.88 डॉलर प्रति बैरल आ गई है तो उपभोक्ता तो यह पूछेंगे ही कि अगर बाजार से कीमतें निर्धारित होती है तो इसे 40 रुपए लीटर बिकना चाहिए। यानी, कीमतों में कटौती होनी चाहिए।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 साल के उच्चतम स्तर पर करों के कारण बढ़े दाम : एसोचैम

नई दिल्ली, 17 सितम्बर (एजेंसिया)। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे उपभोक्ता चिंतित हैं। उनका मानना है जब इन उत्पादों पर लगने वाले करों में बार-बार फेरबदल किया जा रहा हो तो बाजार आधारित कीमतों की अवधारणा का कोई मतलब नहीं है। जब कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं तो देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि 2014 के मई में कच्चे तेल की कीमत 107 डॉलर प्रति बैरल थी, उस वक्त अभी से सस्ता पेट्रोल मिल रहा था।

यह सच है कि पिछले तीन महीनों में कच्चे तेल की कीमतें 45.60 रुपए प्रति बैरल से लेकर अभी तक 18 फीसदी बढ़ी है, जिसका नतीजा है कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 65.40 रुपए से बढ़कर 70.39 रुपए तक पहुंच



गई है। यह बढ़ती कच्चे तेल के दाम में बढ़ती की तुलना में कम है। लेकिन साल 2014 के मई में कच्चे तेल की कीमत 107 रुपए प्रति बैरल पहुंच जाने के बाद भी दिल्ली में 1 जून 2014 को पेट्रोल की कीमत 71.51 रुपए प्रति लीटर थी और ग्राहक यह तुलना कर रहे हैं। एसोचैम के नोट में कहा गया, जब कच्चे तेल की कीमत 107 डॉलर प्रति बैरल थी, तो देश में यह 71.51 रुपए लीटर बिक रही थी। अब जब यह

उपभोक्ताओं की कोई गलती नहीं है। क्योंकि सुधार एकतरफा नहीं हो सकता। अगर कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए: डी. एस. रावत, महासचिव

घटकर 53.88 डॉलर प्रति बैरल आ गई है तो उपभोक्ता तो यह पूछेंगे ही कि अगर बाजार से कीमतें निर्धारित होती है तो इसे 40 रुपये लीटर बिकना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि हालांकि कीमतों को बाजार पर छोड़ा गया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए जानेवाले उत्पाद कर और बिक्री कर या वैट में तेज बढ़ती के कारण सुधार का कोई मतलब नहीं रह गया है। एसोचैम के महासचिव डी. एस.

रावत ने कहा, उपभोक्ताओं की कोई गलती नहीं है। क्योंकि सुधार एकतरफा नहीं हो सकता। अगर कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। चेंबर ने कहा कि हालांकि यह सच है कि सरकार को अवरचना और कल्याण योजनाओं के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन केंद्र और राज्यों की पेट्रोल और डीजल पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। चेंबर ने कहा, इसका असर आर्थिक आंकड़ों पर दिख रहा है। साल-दर-साल आधार पर अगस्त में मुद्रास्फीति की दर क्रमशः 24 फीसदी और 20 फीसदी थी। इससे ऐसे समय में जब उद्योग को निवेश के लिए कम महंगे वित्तपोषण की जरूरत है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को घटाने की संभावनाओं पर असर पड़ता है।

पेट्रोल-डीजल के दाम टैक्स के कारण बढ़े : एसोचैम

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे उपभोक्ता चिंतित हैं। उनका मानना है जब इन उत्पादों पर लगने वाले करों में बार-बार फेरबदल किया जा रहा हो तो बाजार आधारित कीमतों की अवधारणा का कोई मतलब नहीं है। जब कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं तो देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि 2014 के मई में कच्चे तेल की कीमत 107 डॉलर प्रति बैरल थी, उस वक्त अभी से सस्ता पेट्रोल मिल रहा था। यह बढ़ती कच्चे तेल के दाम में बढ़ती कीमतें तुलना में कम हैं। अब जब यह घटकर 53.88 डॉलर प्रति बैरल आ गई है तो उपभोक्ता तो यह पूछें ही कि अगर बाजार से कीमतें निर्धारित होती हैं तो इसे 40 रुपए लीटर बिकना चाहिए। इसमें कहा गया है कि हालांकि कीमतों को बाजार पर छोड़ा गया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए जानेवाले उत्पाद कर और बिक्री कर या टैट में तेज बढ़ती के कारण सुधार का कोई मतलब नहीं रह गया है।

